उत्तर प्रदेश में खुदाई के कार्य पर रोक

917. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर की गई खुदाई में पुरातत्व विभाग को प्राचीन मूर्तियां तथा ऐतिहासिक महत्व की पुराकालीन वस्तुयें मिली हैं ;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग ने खुदाई कार्य रोक दिया है जबकि उन स्थानों पर अनधिकृत रूप से खुदाई का काम होता रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उन स्थानों पर खुदाई का काम पुनः शुरू करने तथा अनधिकृत खुदाई को रोकने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शलजा) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुरमंड, बेटमबार और लाडयुरा (जिला अल्मोड़ा) स्थित महापाषाणकालीन स्थलों, सारनाथ वाराणसी (जिला आपरा) स्थित आद्य एवं-पूर्व ऐतिहासिक स्थल तथा बानार सिंहान कलां (जिला महाराजगंज) और श्रावस्ती (जिला बहराइच), उत्तर प्रदेश स्थित बौद्ध स्थलों पर छोटे पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप विभिन्न कालों के प्राचीन मिट्टी के बर्तनों, अवशेषों और पुरा-वस्तुओं का पता लगाया जा सका है । ये सब उत्खनन कार्य विधिवत अधिकृत थे। प्रतिवर्ष उत्खनन कार्य के कार्यक्रमों को अंतिम रूप पुरा-तत्व के केन्द्रीय सलाहकार मंडल की स्थायी समिति द्वारा दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) कुछ स्थलों पर उत्खनन कार्य का पुनरारम्भ उल्लिखित सक्षम प्राधिकरण और अन्य प्रतिनिधियों का स्वीकृति पर निर्भर करता है।

Payment of regular dues to Delhi University teachers

918. PROF. SAURIN BHATTACHARYA; Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the teachers of college under the Delhi University are not being given the additional D.A. and annual increments;

(b) if so, whether the denial of these regular dues is likely to lead to the complete denial of the teachers' dues; and

(c) whether this is a step towards reverting to dependence on high tution fees, imposing awesome burden on students and guardians?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE): (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

आठवीं पंजवर्षीय योजना के अन्त तक साक्षरता

919. **श्री राम नरेश यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अन्त तक कितने राज्यों में साक्षरता का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है तथा इसमें केन्द्रीय सरकार का कितना अंशदान होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, स्कूल छोड़ जाने वालों के लिये अनौपाचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य 15–35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता दूर करने के व्यापक कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग है। संपूर्ण साक्षरता के लिये क्षेत्रों/जिलों का पता लगाने, परियोजना तैयार करने तथा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की है तथा उन राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की संख्या के संबंध में, जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कोई मूल्यांकन करना कठिन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने के लिये देश के लगभग 350 जिलों (आज तक के 156 जिलों सहित) में संपूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू किया जायेगा। जहां कहीं भी किसी न किसी कारणवश संपूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू करना संभव नहीं है वहां स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक, संस्थाओं तथा नेहरू युवा केन्द्रों आदि द्वारा साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। यह आशा की जाती है कि प्रारंभिक, शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के क्षेत्र में किये गये संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में संपूर्ण साक्षरता दर 70–75 प्रतिशत के बीच पहुंच जायगी जो कि अगले 2–3 वर्षों में संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण स्तर समझा गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में क्रमशः 2880.00 करोड़ तथा 1400.00 करोड़ रु० का अनन्तिम आवंटन किया गया है।

नेशनल बुक ट्रस्ट

920. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भाषावार कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुस्तकों की बिक्री से भाषा वार कितनी आय हुई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान स्वरूप 978.85 लाख रुपये प्रदान किये गये थे।

(ख) न्यास द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की भाषावार संख्या निम्न प्रकार है:–

असमी	106
बंगला	156
अंग्रेजी	281
गुजराती	126
हिंदी	443
कन्नड़	100
मलयालम	77
मराठी	344
उड़िया	57
पंजाबी	103
सिंधी	1
तमिल	79
तेलुगू	85
उर्दू	37
कुल:	1995